

प्रेषक,

पी०सी० शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

(1) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल

(2) सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,
गढ़वाल/कुमायूँ सम्भाग।
देहरादून/हल्द्वानी।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

दिनांक : देहरादून: 18 जून, 2005।

विषय :- विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली के अन्तर्गत रबी/खरीफ खाद्यान्नों के परिवहन दरों के निर्धारण एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति तथा स्थानीय परिवहन हेतु भौतिक शैड्यूल दरों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत खरीदे गये रबी/खरीफ खाद्यान्नों के संचरण की व्यवस्था केन्द्रीय/स्टेट पुल डिपोज तक, जैसी भी स्थिति हो, समय से कर ली जाये। इस सम्बन्ध में निम्नवत प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार बिन्दुवार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये :-

1. परिवहन ठेकेदार की व्यवस्था :-

खाद्यान्न के परिवहन हेतु आर्थिक रूप से सक्षम तथा विभाग में पंजीकृत व्यक्तियों/फर्मों से टेक्निकल विड प्राप्त की जाए तथा जो ठेकेदार अर्हता पूरा करते हो उनकी को निविदा में सम्मिलित किया जाए। ठेकेदारों की नियुक्ति में ऐसे व्यक्तियों/फर्मों को प्राथमिकता दी जाय जिनके पास अपनी निजी ट्रकें हो तथा जिनकी ख्याति/साख अच्छी हो एवं ईमानदार हो। लाईसेंस प्राप्त खाद्यान्न व्यापारियों को यथा संभव ठेकेदार नियुक्त न किया जाए। सम्बन्धित क्व एजेन्सी तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि परिवहन ठेकेदार विचौलियों का कार्य न कर पायें।

परिवहन ठेकेदार के पास जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत एवं वारंश प्रमाण पत्र तथा ठेकेदार के पास कम से कम दो ट्रकों का स्वामित्व भी अवश्य होना चाहिए। संबंधित ठेकेदार द्वारा उत्तरांचल राज्य में कारोबार करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं संबंधित जनपद के जिलाधिकारी की संस्तुति अवश्य प्राप्त करनी होगी। ठेकेदार के पास स्थायी कार्यालय होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त खाद्यान्न परिवहन हेतु ठेके लेने वाली फर्म यदि आयकर विभाग में पंजीकृत है, तो उस दशा में फर्म का पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा उत्तरांचल परिवहन विभाग द्वारा प्रदत्त परिवहन लाईसेंस संबंधित फर्म के पास उपलब्ध होना चाहिए।

इस निमित्त नियुक्त परिवहन ठेकेदारों द्वारा अपने हस्ताक्षर के नमूने एवं अपने सभी ट्रकों की रजिस्ट्रेशन संख्या प्रत्येक क्व केन्द्र पर उपलब्ध करायी जायेगी। परिवहन ठेकेदारों को यह आदेश दिए जायेंगे कि जब भी वह ट्रक को प्रयोग के लिए भेजें तो ट्रक के ड्राइवर के हस्ताक्षर को भी सत्यापित करके भेजें ताकि क्व केन्द्र प्रभारी यह सुनिश्चित कर सकें कि ट्रक परिवहन ठेकेदार के आदेश से ही भेजी गयी है। यदि किसी कारणों से परिवहन ठेकेदार अपने एजेंट को उक्त कार्य हेतु नामित करना चाहता है तो वह उसकी लिखित सूचना देगा और उसके हस्ताक्षर के नमूने को सम्बन्धित अधिकारी को

क्रमशः दो गर....



अपित करेगा।

2. परिवहन दरों का निर्धारण :-

परिवहन की दरों का निर्धारण सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। अतएव विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत समस्त जिलाधिकारी स्वी/खरीफ खाद्यान्नों के लिए परिवहन दरें समय से निर्धारित कर दें ताकि ठेकेदारों के अभाव में क्रय केन्द्रों पर भेड़/धान का न तो जमाव हो सके और न ही क्रय एजेंसियों को तदर्थ व्यवस्था करने के लिए बाध्य होना पड़े।

परिवहन ठेकेदारों के लिए दरों के निर्धारण में एकस्यता रखने, अनावश्यक प्रतिस्पर्धा को दूर करने तथा दुर्विनियोग आदि को रोकने हेतु जिलाधिकारियों द्वारा जनपद की वास्तविक तथा व्यावहारिक स्थानीय दूरी को संज्ञान में रखते हुये सम्भागीय आतायात अधिकारी, भारतीय खाद्य निगम, पी०सी०एफ०, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, ग्रामीण एग्री, उपभोक्ता सहाकारी संघ तथा सम्भागीय खाद्य नियंत्रक से तत्समय परिवहन की प्रचलित बाजार दरें (डिटेंशन अवधि) ज्ञात करने के पश्चात् दरें तय की जायेगी। इस सम्बन्ध में यह भी देखा जाना आवश्यक होगा कि निर्धारित परिवहन दरें पूरे जनपद हेतु व्यावहारिक हों, जिससे की सभी क्रय संस्थाओं को परिवहन ठेकेदार उपलब्ध हो सकें। परिवहन ठेकेदारों के लिए परिवहन की दरें तथा ट्रकों की व्यवस्था के लिए शासनादेश संख्या-पी-372/29 गेट 1.5(12)/79 दिनांक 09-04-1979 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

3. ठेकेदारों की नियुक्ति :-

परिवहन ठेकेदारों को टेण्डर के आधार पर नियुक्त करने में निम्नलिखित माप-दण्ड रखा जाना सुनिश्चित किया जाये :-

- (अ) परिवहन ठेकेदारों हेतु अर्हता निर्धारित की जाए तथा उन ठेकेदारों का ही पंजीकरण विभाग में किया जाए जो आर्थिक रूप से सक्षम, अच्छी ख्याति वाले व ईमानदार हैं तथा उनके पास स्वयं अपने ट्रक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। पंजीकरण से पूर्व ठेकेदारों के पूर्ववृत्त का सत्यापन परिवहन विभाग से करा लिया जाए तथा ऐसे ठेकेदारों का पंजीकरण न किया जाए जो संदिग्ध वृत्त वाले हों अथवा जिनके विरुद्ध खाद्यान्न के दुर्विनियोग के मामले पूर्व से ही प्रचलित हों अथवा जो इन अपराधों के लिए न्यायालय में दोषी सिद्ध हुए हों।
- (ब) निविदा से पूर्व परिवहन ठेकेदारों से "टेक्निक्ल ब्रिड" प्राप्त की जाए तथा जो ठेकेदार अर्हता को पूरा करते हैं उनकी को निविदा में सम्मिलित किया जाए।
- (स) भारत सरकार द्वारा जिलाधिकारियों द्वारा निर्धारित परिवहन दर से अधिक दर पर परिवहन व्यय कि प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी। इसलिए टेण्डर के समय जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर के आधार पर ही निविदायें स्वीकार की जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत दर से अधिक दर की निविदा को निरस्त करते हुये सम्बन्धित को सूचित कर दिया जाये।
- (द) केन्द्रों से खाद्यान्न के संचरण के समय चोरी/गबन/दुर्विनियोग को समाप्त करने के उद्देश्य से यथासम्भव जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दरों पर ही परिवहन ठेकेदार नियुक्त किये जाए। प्रतिस्पर्धा के वर्तमान समय में यह सम्भावना रहेगी कि टेण्डर के समय जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर से कम की दरें प्रस्तुत की जायें, जिसको स्वीकृत करने की दशा में सम्बन्धित संस्था को ऑडिट आपत्ति पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत दर से 05 प्रतिशत (पाँच प्रतिशत) कम की सीमा से कम दर की निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा। 05 प्रतिशत से अधिक कमी वाली दरें अव्यवहारिक मानी जायेगी तथा उन्हें निरस्त करते हुये सम्बन्धित को सूचित कर दिया जाये।
- (य) शासन के वित्त विभाग द्वारा टेण्डर प्रतिक्रिया एवं पारदर्शिता निर्गत शासनादेश संख्या-ए-1-1173/दस-2001-10(55)/2000 दिनांक 27-04-2001 के क्रम में प्राप्त टेण्डरों के

निविदाओं से निर्गोपणन सामान्यतः न किया जाए। एक से अधिक एक ही दर दी जाने वाली निविदा को पदाकारों के समक्ष लाटरी के द्वारा अन्तिम रूप दिया जाएगा।

4. डेकेदारों से अनुबंध :-

इस सम्बन्ध में शारनादेश संख्या-पी० 372/29 में 15(12)/79 दिनांक 09-04-1979 के प्रस्तर 8 के अनुसार कार्यवाही की जाए तथा प्रत्येक क्रय केन्द्र पर प्रोविजन की खरीद के आधार पर ट्रकों की आवश्यकता का आकलन करते हुए अनुबंध पत्र में यह शर्त अवश्य जोड़ी जाए कि न्यूनतम संख्या में ट्रकों की उपलब्धता उसके प्रायः सदैव सुनिश्चित रहनी चाहिए तथा भी ध्यान रखा जाए कि डेकेदार के अनुबंध पत्र भराने के बाद ही परिवहन कार्य करना प्रारम्भ किया जाए।

5. जमानत की धनराशि :-

नियुक्त परिवहन डेकेदारों से रुपये 25,000.00 (रुपये पच्चीस हजार मात्र) की नकद जमानत और क्रय केन्द्र पर जिस दिन की सर्वाधिक खरीद हुई हो, समेत की मात्रा का उल्लेख करते हुए उसकी मात्रा के मूल्य के 10 प्रतिशत की धनराशि के बराबर बैंडोलनी बाण्ड लिया जाना सुनिश्चित किया जाये। यदि बीमा कम्पनियाँ बैंडोलनी बाण्ड निर्गत करती हों तो सम्बन्धित डेकेदार से उस धनराशि की बैंक गारण्टी अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में लिये जाने की व्यवस्था की जा सकती है।

अपवाद स्वरूप जहाँ क्रय की मात्रा काफी कम होने के कारण परिवहन कार्यों का सम्पादन कराने में कठिनाई हो रही हो वहाँ सम्भागीय खाद्य नियंत्रक अपने निम्नलिखित से अन्य प्रतिबन्धों को यथावत रखते हुये जमानत की धनराशि न्यूनतम रुपये 15,000 (रुपये पच्चीस हजार मात्र) तक रख सकते हैं, लेकिन इस कारण यदि शारन को क्षति होती है तो उसके लिये सम्भागीय खाद्य नियंत्रक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

मुझे यह भी स्पष्ट करना है कि अनुबंध तथा जमानत पर स्वयं शुल्क एकर की अनुसूची में निर्धारित दर के अनुसार लगेगा जो परिवहन डेकेदार द्वारा कटव किया जाएगा।

6. क्षति की वसूली :-

यदि परिवहन डेकेदार से खाद्यान्न की क्षति होती हो तो उस क्षतिग्रस्त खाद्यान्न का मूल्य के 1.5 (डेढ़) गुना मूल्य की धनराशि के बराबर क्षतिपूर्ति करायी जाये। इस शर्त की भी अनुबंध की शर्तों में सम्मिलित किया जाये। ऐसे सभी मामलों का विवरण जिला नियंत्रक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल को भेजा जायेगा।

खाद्य विभाग के केन्द्रों पर खाद्यान्न/लेकी चीनी मृत स्कंधों के हैण्डलिंग एवं स्थानीय परिवहन के शीड्यूल की सांकेतिक दरें संलग्नक में उल्लिखित मानक के आधार पर होंगी।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय आय व्ययक में लेखाशीर्षक "4408" खाद्य भण्डारण और भण्डागारण पर पूर्ण परिचय-आयोजनेत्तर-01- खाद्य 101 खरीद और पूर्ण 03-अन्नापूर्ति योजना 31 सामग्री तथा सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग की सहमति से इस प्रतिबन्ध के साथ जारी किए जा रहे हैं कि उक्त व्यय भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार होगा तथा इसकी प्रमाणित करा ली जाएगी। उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार परिवहन दरों का निर्धारण एवं परिवहन डेकेदारों की नियुक्ति तथा उसके अनुबंध पत्र भराने आदि की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

संलग्नक :- यथोपरि

भवदीय,

(पी०सी० शर्मा)

सचिव।

अस्थायी कार्यालय

संख्या : १६६ (१)/XIX/2005, तददिनांक ।

प्रतिलिपि : गजलेखाकार, उत्तरांचल को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(एम०सी० उप्रेती)
अपर सचिव।

संख्या १६६ (१)/XIX/2005 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
2. परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल देहरादून ।
3. आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल ।
4. अपर आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल ।
5. समस्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, उत्तरांचल ।
6. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, उत्तरांचल ।
7. वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक विभाग, उत्तरांचल ।
8. मुख्य विपणन अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल ।
9. समस्त वरिष्ठ/संभागीय वित्त अधिकारी (खाद्य), कुमायूँ/गढ़वाल संभाग ।
10. समस्त संभागीय विपणन अधिकारी, खाद्य विभाग ।
11. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, देहरादून ।
12. प्रबन्ध निदेशक, समस्त क्रय संस्थाएं, उत्तरांचल ।
13. वित्त अनुभाग-3 उत्तरांचल शासन ।
14. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, खाद्य उत्तरांचल ।
15. निदेशक, एन०आईसी० राधियालय परिसर, देहरादून/गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(एम०सी० उप्रेती)
अपर सचिव।